



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड IV

PART III—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2019/ज्येष्ठ 17, 1941

No. 199]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2019/JYAISTHA 17, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 14 मई, 2019

सं. टीएमपी/77/2018-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु वीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएमपी/77/2018-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मार्च, 2019 के 29वें दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु वीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 4 दिसंबर 2018 से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएमपी/9/2016-वीपीटी दिनांक 21 जून 2016 द्वारा संशोधित दरमानों के साथ वीपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव से संबंधित एक आदेश पारित किया था। यह आदेश 22 जुलाई 2016 को राजपत्र सं. 305 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश प्रशुल्क वैधता अवधि 31 मार्च 2019 तक निर्धारित करता है।

2.2. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वीपीटी के मौजूदा दरमानों में वीपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रशुल्क नहीं दिया गया है।

3.1. वीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में की गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:—

- (i) आईपीए की शासी निकाय बैठक में निर्णय लिया गया है कि पत्तनों को कंटेनरों के आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और सीमाशुल्क द्वारा यथा आज्ञापित मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टमों की खरीद और संस्थापना करनी चाहिए। निविदाकरण प्रक्रिया आईपीए द्वारा शुरू की गई थी और पत्तनों को निदेश दिया गया है कि वे आईपीए द्वारा अंतिम रूप दिए गए एल-1 बोलीदाता को खरीद आदेश दें।

- (ii) पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने पत्र सं. पीडी-14033/113/2015-पीडी.वी. दिनांक 12-7-2018 (परिशिष्ट-क रूप में प्रेषित) द्वारा पत्तन में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग की संस्थापना के लिए परियोजना के क्रियान्वयन पर 12 जून 2018 को आईपीए में हुई बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख किया है। एमओएस ने जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी), वीपीटी, पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी), न्यू मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के अध्यक्षों को संप्रेषित उक्त पत्र में निर्णय संप्रेषित करते हुए कि पत्तनों को वसूली के लिए लागत हेतु मानक दरों का अनुसरण करना होगा तथा प्रशुल्क के निर्धारण हेतु टीएमपी के सामने प्रस्ताव रखना होगा।
- (iii) इस परिप्रेक्ष्य में, वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने संकल्प सं. 142/2017-18 (परिशिष्ट-ख रूप में प्रेषित) द्वारा मै. स्मिथस डिटेक्शन (एशिया पसिफिक) प्रा. लि. से 8 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों, कर तथा शुल्कों के लिए रु. 10,15,38,775 (रु. 10.15 करोड़) सहित एक मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की खरीद, संस्थापन तथा शुरू करने के लिए रु. 29.68 करोड़ की कुल राशि अनुमोदित की थी। न्यासी बोर्ड ने एमओएस दिशानिर्देशों के अनुसार टीएमपी अनुमोदित दरों के अनुसार अवसररचना अधिभार, यदि कोई हो, की वसूली करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया था। उपस्कर की संस्थापना के लिए कार्रवाई भी शुरू की गई है।
- (iv) समान सुविधा के लिए प्रशुल्क किसी अन्य महापत्तन में उपलब्ध नहीं है। वैसे, सुविधा की दरित क्षमता के आधार पर प्रशुल्क के निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रशुल्क प्रक्रिया दिशानिर्देश, 2015 के खंड 5.7.1 के अनुसार तैयार किया गया है। वीपीटी ने वीपीटी में इस सुविधा के लिए प्रशुल्क अधिसूचित करने का अनुरोध किया है।

3.2. प्रशुल्क के लिए लागत निर्धारण निम्नलिखित है:

- (i) पूंजी लागत:

I.	एक्स-रे स्कैनर की पूंजी लागत (जीएसटी अतिरिक्त)	15,48,71,376
II.	सिविल कार्यों की पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	1,81,90,940
III.	रोशनी सहित बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	21,15,830
IV.	फाइबर तथा सीसीटीवी नेटवर्क हेतु पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	5,97,990
	कुल पूंजी लागत	17,57,76,136

टिप्पणियाँ :

- सिविल तथा उपस्कर लागत के पूंजी लागत पर 5 प्रतिशत की विविध लागत के लिए कोई प्राक्धान नहीं किया गया है क्योंकि लागतें वास्तविक कार्य आदेश मूल्य के अनुसार हैं।
- आईपीए द्वारा संप्रेषित मदों की कीमत अनुसूची तथा मात्राओं की अनुसूची की लागत मदें जीएसटी सहित हैं। तथापि, इसे अलग रखा गया है क्योंकि सिविल कार्यों की पूंजी लागत के सिवाय जीएसटी को क्रेडिट लिया जाएगा।

- (ii) दरित क्षमता:

एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की दरित क्षमता कार्यक्षेत्र के अनुसार 40 फीट कंटेनरों की 20 संख्या प्रति घंटा (परिचालन के माध्यम से एक तरफ के आधार पर) है।

अतः, प्रतिवर्ष क्षमता निम्नलिखित परिगणित होती है:

$$0.7 \times 365 \text{ दिन} \times 24 \text{ घंटे} \times 20 \text{ संख्याएं} \times 2 \text{ टीईयू} = 245,280 \text{ टीईयू प्रतिवर्ष।}$$

- (iii) परिचालन तथा अनुरक्षण लागत:

- (क) (i) बिजली:

सुविधा के परिचालन के लिए बिजली उपभोग की लागत के लिए रु. 18,58,305/- प्रतिवर्ष की राशि का अनुमान लगाया गया है।

- (ii) ईंधन:

यह सुविधा किसी ईंधन का उपभोग नहीं करती है इसलिए शून्य माना गया है।

- (ख) मरम्मत और अनुरक्षण:

- (i) सिविल परिसंपत्तियों की मरम्मत और अनुरक्षण मानदंडों के अनुसार सभी सिविल परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत की दर से अनुमानित किया गया है। सिविल कार्यों की कुल लागत रु. 1,81,90,940/- है। वैसे सिविल परिसंपत्तियों की मरम्मत और अनुरक्षण की लागत रु. 1,81,909/- परिगणित होता है।

- (ii) पुर्जों सहित अभियांत्रिक तथा बिजली उपकरण:

- (क) एक्स-रे स्कैनर के लिए गारंटी अवधि दो वर्ष है। 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी सहित 8 वर्षों की गारंटी-परचात अवधि के लिए कुल अनुरक्षण लागत रु. 10,15,38,775/- और आईजीएसटी अतिरिक्त 8 वर्षों के लिए रु. 8,60,49,809/- है। इस प्रकार, एक्स-रे स्कैनर की एएमसी के लिए औसत व्यय प्रतिवर्ष आईजीएसटी अतिरिक्त रु. 8,60,49,809/- ÷ 8 = 1,07,56,226 परिगणित होता है।

- (ख) इलैक्ट्रिकल उपकरण की मरम्मत तथा अनुरक्षा और फाइबर तथा सीसीटीवी नेटवर्क मानदंडों के अनुसार पूंजी लागत पर 2 प्रतिशत की दर से सुविचारित किया गया है। इस प्रकार, रु. 27,13,820/- पर आर एंड एम लागत रु. 54,276/- प्रतिवर्ष परिगणित होता है।

- (ग) बीमा:
सकल अचल परिसंपत्तियों का मूल्य रु. 17,57,76,136/- है। मानदंडों के अनुसार सकल अचल परिसंपत्तियों पर बीमा 1 प्रतिशत की दर से रु. 17,57,761/- प्रतिवर्ष परिगणित होता है।
- (घ) मूल्यहास:
सुविधा का वर्गीकरण कम्पनी अधिनियम के "IV. संयंत्र तथा मशीनरी (क) विशिष्ट उद्योगों के अधीन अनाच्छादित सतत् प्रक्रिया संयंत्र से इतर संयंत्र तथा मशीनरी" के अधीन सुविचारित किया गया है जिसके लिए विनिर्दिष्ट जीवनकाल 15 वर्ष है। मूल्यहास की तदनुसार गणना की गई है जोकि रु. 1,17,18,409/- प्रतिवर्ष परिगणित होती है।
- (ङ) लाइसेंस शुल्क और अन्य व्यय:
लाइसेंस शुल्क और अन्य व्ययों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह सुविधा डीजीएफटी तथा सीमाशुल्क की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने परिसर में वीपीटी की लागत पर संस्थापित की जा रही है। सीमाशुल्क द्वारा स्वयं अपने द्वारा परिचालित किए जा रहे अन्य स्थानों पर पहले संस्थापित उन एमएक्ससीएस के लिए समान लाइनों में प्रत्येक पाली में अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ की सीमाशुल्क उपयुक्त मैनिंग करेगा।
- (iv) आरओसीई:
टीएमपी मानदंडों के अनुसार, 16 प्रतिशत आरओसीई स्वीकृत किया गया है। तथापि, पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. पीडी-14033/113/2015-पीडी.वी. दिनांक 12-7-2018 में बताया गया है कि यह निर्णय लिया गया था कि पत्तन को लागत वसूली के लिए मानक दरों का अनुसरण करना होगा और प्रशुल्क के निर्धारण के लिए टीएमपी के समक्ष प्रस्ताव रखना होगा। उपस्कर का जीवनकाल 15 वर्ष है। वैसे, इसके 15 वर्षों के जीवनकाल के दौरान उपस्कर की लागत वसूल करने के लिए, आरओसीई 6.67 प्रतिशत (100/15 वर्ष) परिगणित किया गया है।
- (v) वार्षिक राजस्व अपेक्षा:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	बिजली उपभोग	18,58,305
2.	सिविल परिसंपत्तियों की मरम्मत और अनुरक्षण	1,81,909
3.	एक्स-रे स्कैनर की मरम्मत और अनुरक्षण	1,07,56,226
4.	इलैक्ट्रिकल उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	54,276
5.	बीमा	17,57,761
6.	मूल्यहास	1,17,18,409
7.	आरओसीई (लागत वसूली 15 वर्षों में)	1,17,18,409
	कुल	3,80,45,295

(vi) प्रस्तावित प्रशुल्क:

अतः, प्रशुल्क प्रति टीईयू = रु.3,80,45,295 ÷ 2,45,280 = रु.155.11 प्रति टीईयू।

4. प्रस्ताव की पावती देते समय, वीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 21 दिसंबर 2018 द्वारा अनुरोध किया गया था कि निम्नलिखित कुछ बिन्दुओं पर सूचना/स्पष्टीकरण 4 जनवरी 2019 तक भेजे। इसके लिए अनुस्मारक दिनांक 1 फरवरी 2019 दिया गया था। प्रत्युत्तर में, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2019 द्वारा सूचना/स्पष्टीकरण भेजा था। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उसपर वीपीटी द्वारा प्रेषित टिप्पणियों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:-

क्र.सं.	हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	वीपीटी द्वारा प्रेषित उत्तर				
I	वीपीटी द्वारा प्रशुल्क परिकलन:					
	एक्स-रे कंटेनर स्कैनर के लिए परिचालन लागतें:					
(क)	बिजली लागत:					
	वीपीटी ने रु. 18,58,305 प्रतिवर्ष की लागत से बिजली लागत का अनुमान लगाया है। पत्तन ने बताया है कि विस्तृत विवरण अनुबंध-2 रूप में संलग्न किया गया है। तथापि, पत्र दिनांक 4 दिसंबर 2018 के साथ ऐसा विवरण संलग्न नहीं पाया गया। वीपीटी बिजली लागत का अनुमान लगाने के लिए सुविचारित बिजली की इकाई दर और बिजली उपभोग के लिए आधार के साथ बिजली उपभोग देते हुए बिजली लागत की विस्तृत गणना भेजे। यह भी पुष्टि करें कि क्या बिजली की इकाई दर प्रचलित दर है और परिकलन में अंगीकृत इकाई दर के समर्थन में पिछले तीन महीनों के बिजली बिलों की प्रतियां भेजें।	अनुमानित बिजली लागत का विस्तृत विवरण नीचे तालिकाबद्ध किया गया है। यह पुष्टि की जाती है कि इकाई दर बिजली प्रचलित दर है। पिछले 4 महीनों के लिए बिलों की प्रतियां संलग्न की गई हैं। I. बिजली आपूर्ति व्यवस्थाएँ: <table><tr><td>(i)</td><td>लाइटिंग 200 वाट x 26 सं.</td><td>5.2 केडब्ल्यू x 12 घंटे</td><td>62.40 केडब्ल्यूएच</td></tr></table>	(i)	लाइटिंग 200 वाट x 26 सं.	5.2 केडब्ल्यू x 12 घंटे	62.40 केडब्ल्यूएच
(i)	लाइटिंग 200 वाट x 26 सं.	5.2 केडब्ल्यू x 12 घंटे	62.40 केडब्ल्यूएच			

		<table><tr><td>(ii)</td><td>15 ए बिजली सॉकेट X 04 सं.</td><td>12 केडब्ल्यू x 06 घंटे</td><td>72.00 केडब्ल्यूएच</td></tr><tr><td>(iii)</td><td>18 वॉट टीएल x 10 सं.</td><td>0.18 केडब्ल्यू x 18 घंटे</td><td>3.24 केडब्ल्यूएच</td></tr><tr><td>(iv)</td><td>50 वॉट सी/एफ x 10 सं.</td><td>0.5 केडब्ल्यू x 18 घंटे</td><td>9.00 केडब्ल्यूएच</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>146.64 केडब्ल्यूएच / दिन</td></tr></table> <p>बिजली उपभोग/वार्षिक: 150 X 365: 54750 इकाईयां</p> <p>व्यय/वर्ष: 54750 X 6.38 (अर्थात् 6.32+0.06) रु. <u>3,49,305/-</u></p> <p>II. एमएक्ससीएस बिजली उपभोग:</p> <table><tr><td>बिजली आवश्यकता</td><td>40 केवीए X 0.9</td><td>36 केडब्ल्यू</td></tr><tr><td></td><td>36 KW X 18 Hrs</td><td>648 केडब्ल्यूएच/दिन</td></tr><tr><td>एमएक्ससीएस बिजली उपभोग/वार्षिक</td><td></td><td>648 x 365 : 2,36,520 इकाईयां</td></tr><tr><td>Expenditure/ Annum :</td><td>236520 x 6.38 (अर्थात् 6.32 + 0.06)</td><td>रु.15,09,000/-</td></tr></table> <p>(क) बिजली उपभोग/वार्षिक (एमएक्ससीएस के साथ) – (I + II) = रु. 18,58,305/-</p> <p>(ख) बिजली उपभोग/वार्षिक (एमएक्ससीएस के बिना) – I = रु. 3,49,305/-</p>	(ii)	15 ए बिजली सॉकेट X 04 सं.	12 केडब्ल्यू x 06 घंटे	72.00 केडब्ल्यूएच	(iii)	18 वॉट टीएल x 10 सं.	0.18 केडब्ल्यू x 18 घंटे	3.24 केडब्ल्यूएच	(iv)	50 वॉट सी/एफ x 10 सं.	0.5 केडब्ल्यू x 18 घंटे	9.00 केडब्ल्यूएच				146.64 केडब्ल्यूएच / दिन	बिजली आवश्यकता	40 केवीए X 0.9	36 केडब्ल्यू		36 KW X 18 Hrs	648 केडब्ल्यूएच/दिन	एमएक्ससीएस बिजली उपभोग/वार्षिक		648 x 365 : 2,36,520 इकाईयां	Expenditure/ Annum :	236520 x 6.38 (अर्थात् 6.32 + 0.06)	रु.15,09,000/-
(ii)	15 ए बिजली सॉकेट X 04 सं.	12 केडब्ल्यू x 06 घंटे	72.00 केडब्ल्यूएच																											
(iii)	18 वॉट टीएल x 10 सं.	0.18 केडब्ल्यू x 18 घंटे	3.24 केडब्ल्यूएच																											
(iv)	50 वॉट सी/एफ x 10 सं.	0.5 केडब्ल्यू x 18 घंटे	9.00 केडब्ल्यूएच																											
			146.64 केडब्ल्यूएच / दिन																											
बिजली आवश्यकता	40 केवीए X 0.9	36 केडब्ल्यू																												
	36 KW X 18 Hrs	648 केडब्ल्यूएच/दिन																												
एमएक्ससीएस बिजली उपभोग/वार्षिक		648 x 365 : 2,36,520 इकाईयां																												
Expenditure/ Annum :	236520 x 6.38 (अर्थात् 6.32 + 0.06)	रु.15,09,000/-																												
(ख)	पुर्जों सहित अभियांत्रिक तथा बिजली उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण																													
(i)	वीपीटी ने बताया है कि एक्स-रे कंटेनर स्कैनर का जीवनकाल 15 वर्ष है और उपस्कर की गारंटी अवधि 2 वर्ष है। वीपीटी ने रु. 1,07,56,226/- प्रतिवर्ष की दर से अनुरक्षण पर विचार किया है जोकि रु. 8,60,49,809 की दर से अनुमानित 8 वर्षों की अवधि की आनुपातिक कुल अनुरक्षण लागत है। वीपीटी द्वारा प्रेषित अनुबंध-1 से यह देखा गया है कि दो वर्षों की गारंटी अवधि के बाद, स्कैनर की वार्षिक अनुरक्षण लागत 10 प्रतिशत की दर से वर्ष दर वर्ष बढ़कर प्रथम वर्ष में रु. 88,78,958/- से आठ वर्ष में रु.29,68,74,836/- हो जाएगी। इस संदर्भ में, कृपया निम्नलिखित स्पष्ट करें:-																													
(क)	परिसंपत्ति के जीवनकाल की शेष अवधि [15-(2+8)=5] पर विचार नहीं करने के कारण।	फर्म ने अपने प्रस्ताव में केवल 8 वर्षों की गारंटी अवधि के बाद वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के ब्योरे भेजे हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि गारंटी अवधि के बाद एमसी प्रभारों में 8 वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है। वैसे, फर्म द्वारा विनिर्दिष्ट 8 वर्षों की अवधि के लिए एमसी की औसत एमसी प्रतिवर्ष सुविचारित की गई है। टीएमपी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क अपफ्रंट है और लागू सूचकांकन के साथ शेष पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।																												
(ख)	अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 में निर्धारित मानदंडों को लागू नहीं करने के कारण ज्यादा विशेष रूप से स्पष्ट करें क्योंकि पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) का पत्र सं. पीडी-14033/113/2015-पीडी-वी दिनांक 12 जुलाई 2018 वीपीटी से एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की लागत वसूली के लिए मानदंड संबंधी दरों का निर्णय करने की अपेक्षा करता है।	चूंकि फर्म ने गारंटी अवधि के बाद 8 वर्षों के लिए एमसी स्पष्ट रूप से दर्शाई है, इसलिए एमसी प्रतिवर्ष के लिए 8 वर्ष अवधि की औसत पर विचार करने की राय व्यक्त की गई है।																												
(ग)	चूंकि मानदंड संबंधी प्रशुल्क एमओएस की सलाह के अनुसार लागत की वसूली के लिए निर्धारित किया जाना है, इसलिए कंटेनर स्कैनर के लिए मानदंड संबंधी प्रशुल्क 3 वर्षों में एक बार आवधिक समीक्षा के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत के वार्षिक सूचकांकन के अधीन स्कैनर की सम्पूर्ण जीवनकाल अवधि के लिए स्थिर होना चाहिए। वीपीटी से अनुरोध है कि इस संबंध में अपनी टिप्पणियां भेजे।	प्रशुल्क 2008 दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित किया गया है, जिसमें खंड 2.8 के अनुसार प्रशुल्क परिचालन की अवधि के लिए टीएमपी द्वारा यथा अधिसूचित डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की सीमा तक सूचकांकित किया जाएगा और 3 वर्षों में एक बार समीक्षा नहीं की जाएगी।																												

(घ)	एक्स-रे कंटेनर स्कैनर के परिचालन के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क दर वीपीटी के सामान्य दरमान (एसओआर) में शामिल किया जाना चाहिए जोकि प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन प्रत्येक 3 वर्षों में समीक्षा के अधीन है। ऐसी स्थिति में, प्रस्तावित प्रशुल्क पर पहुंचने के समय 2 वर्षों की गारंटी के बाद 8 वर्षों की अवधि के लिए कुल अनुरक्षण लागत की औसत पर विचार करने का कारण स्पष्ट करें।	जैसाकि ऊपर दिया गया है।																									
(ङ)	यह स्वीकार करते हुए कि यह मद वारंटी के अधीन है और प्रथम दो वर्षों के लिए “शून्य” अनुमान लगाया जा रहा है, वीपीटी प्रथम दो वर्षों के लिए स्कैनर की अनुरक्षण लागत के अलावा स्कैनर के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क और रु. 30.68 (अर्थात् रु. 7524541/245280 टीईयू) की दर से स्कैनर की अनुरक्षण की प्रति टीईयू लागत को लेते हुए तीसरे वर्ष के लिए पृथक प्रशुल्क पर विचार करें।	2008 दिशानिर्देशों के अनुसार, एक ही सुविधा के लिए दो भिन्न-भिन्न प्रशुल्कों के निर्धारण का प्रावधान नहीं है।																									
(ग)	मूल्यहास: वीपीटी ने 15 वर्षों की अवधि के लिए कुल पूंजी लागत पर रु. 1,17,18,409 की दर से मूल्यहास का अनुमान लगाया है। मूल्यहास पर पहुंचने के लिए 15 वर्षों की अवधि के लिए अनुमानित कुल पूंजी लागत रु. 17,57,76,136 को 15 वर्षों से विभाजित किया गया है। वीपीटी ने बताया है कि उसने संयंत्र तथा मशीनरी के लिए लागू IV- सामान्य दर के अधीन कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अधीन सुविधा के वर्गीकरण पर विचार किया था। इस संबंध में, निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट करें:	विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए अलग-अलग जीवनकाल मानदंड की विधिवत् गणना करते हुए मूल्यहास निम्नवत् संशोधित किया गया है:- <div>(रुपयों में)</div> <table><tr><td>I.</td><td>एक्स-रे स्कैनर की पूंजी लागत (जीएसटी अतिरिक्त)</td><td>15,48,71,376</td><td>15 वर्ष</td><td>1,03,24,758</td></tr><tr><td>II.</td><td>सिविल कार्यों की पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)</td><td>1,81,90,940</td><td>60 वर्ष</td><td>3,03,182</td></tr><tr><td>III.</td><td>रोशनी सहित बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने की पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)</td><td>21,15,830</td><td>10 वर्ष</td><td>2,11,583</td></tr><tr><td>IV.</td><td>फाइबर और सीसीटी नेटवर्क के लिए पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)</td><td>5,97,990</td><td>6 वर्ष</td><td>99,665</td></tr><tr><td></td><td></td><td>17,57,76,136</td><td></td><td>1,09,39,188</td></tr></table>	I.	एक्स-रे स्कैनर की पूंजी लागत (जीएसटी अतिरिक्त)	15,48,71,376	15 वर्ष	1,03,24,758	II.	सिविल कार्यों की पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	1,81,90,940	60 वर्ष	3,03,182	III.	रोशनी सहित बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने की पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	21,15,830	10 वर्ष	2,11,583	IV.	फाइबर और सीसीटी नेटवर्क के लिए पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	5,97,990	6 वर्ष	99,665			17,57,76,136		1,09,39,188
I.	एक्स-रे स्कैनर की पूंजी लागत (जीएसटी अतिरिक्त)	15,48,71,376	15 वर्ष	1,03,24,758																							
II.	सिविल कार्यों की पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	1,81,90,940	60 वर्ष	3,03,182																							
III.	रोशनी सहित बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने की पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	21,15,830	10 वर्ष	2,11,583																							
IV.	फाइबर और सीसीटी नेटवर्क के लिए पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	5,97,990	6 वर्ष	99,665																							
		17,57,76,136		1,09,39,188																							
(i)	कुल पूंजी लागत में सिविल कार्य तथा बिजली कार्य शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 विभिन्न प्रकृति की परिसंपत्तियों के लिए पृथक-पृथक जीवनकाल मानदंड उपलब्ध करवाता है। अतः वीपीटी परिसंपत्ति की प्रकृति पर निर्भर करते हुए मूल्यहास की प्रासंगिक दर लागू करें और इसका संदर्भ दें।																										
(ii)	5 प्रतिशत स्क्रैप मूल्य पर विचार करने के बाद 15 वर्षों के जीवनकाल मानदंड लागू करते हुए कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन संयंत्र तथा मशीनरी के लिए मूल्यहास दर एकल पाली के लिए 6.33 प्रतिशत परिगणित होती है। दोगुनी पाली के लिए, मूल्यहास दर में 50 प्रतिशत और तीन पालियों के लिए 100 प्रतिशत वृद्धि किए जाने की जरूरत है। चूंकि वीपीटी ने 24 घंटों के एक दिन के लिए एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की सर्वोत्तम क्षमता मूल्यांकित की है, इसलिए वीपीटी उपर्युक्त अवलोकन के आलोक में मूल्यहास के अनुमान की समीक्षा करें।	सुविधा के भाग के रूप में प्रस्तावित सभी परिसंपत्तियां एनईएसडी श्रेणी के अधीन आती हैं जिनके लिए कम्पनी अधिनियम के अनुसार कोई अतिरिक्त पाली मूल्यहास नहीं दिया गया है। वैसे कोई अतिरिक्त पाली मूल्यहास परिकल्पित नहीं किया गया है।																									
(घ)	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई):																										
	वीपीटी ने उपस्कर की लागत की वसूली के लिए 6.67 प्रतिशत आरओसीई का प्रस्ताव किया है। वीपीटी उपस्कर की लागत की वसूली करने के लिए लागत गणना में मूल्यहास पर पहले ही विचार कर चुका है। अतः, प्राधिकरण द्वारा अनुमत 16 प्रतिशत आरओसीई की अपेक्षा गणना में सुविचारित आरओसीई के निम्नतर स्तर का औचित्य बतायें।	मूल्यहास ओ एंड एम लागत के घटक रूप में ही सुविचारित किया गया है। परियाजना के जीवनकाल के दौरान सुविधा की पूंजी लागत की वसूली करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, आरओसीई $100/15=6.67\%$ रूप में सुविचारित किया गया है। आरओसीई का निम्नतर स्तर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए सुविचारित किया गया है:- (i) किसी प्रतिलाभ के बिना अवसंरचना अधिभार की वसूली द्वारा लागत की वसूली करना क्योंकि यह डीजीएफटी की अनिवार्य अपेक्षा है। (ii) साध्य स्तर तक लॉजिस्टिक लागत को कम करना।																									
II.	दरमान: पत्तन ने वीपीटी ने मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रशुल्क शासित करने वाली शर्तें नहीं भेजी हैं। अतः वीपीटी प्रशुल्क को शासित करने वाली शर्तें, यदि कोई हो, दें।	सुविधा पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी: (i) एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के लिए अवसंरचना अधिभार/प्रशुल्क																									

	<p>टीईयू में अभिव्यक्त सभी आयात ओवरसीज कंटेनर पर लागू है।</p> <p>(ii) प्रशुल्क/अवसंरचना अधिभार को 1 जनवरी 2019 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक ही मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा। प्रशुल्क सीमा का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमा प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू होगी।</p>
--	--

5. निर्धारित परामर्श प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी के प्रस्ताव दिनांक 4 दिसंबर 2018 की प्रतिलिपि संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों/आयातकों/सीएफएस एजेंटों को परिचालित की गई थी। तथापि, अनुस्मारक दिनांक 15 जनवरी 2019 के बावजूद हमें उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों/आयातकों/सीएफएस एजेंटों से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

6.1. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 22 जनवरी 2019 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी ने अपने प्रस्ताव का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। उपयोक्ताओं और वीपीटी ने संयुक्त सुनवाई में अपने निवेदन पेश किए थे।

6.2. संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, हमारे पत्र दिनांक 1 फरवरी 2019 द्वारा वीपीटी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था:—

- (i) संयुक्त सुनवाई में, कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल) ने लिखित निवेदन दिनांक 22 जनवरी 2019 पेश किए थे। सीसीआईएल द्वारा किए गए लिखित निवेदन की प्रति वीपीटी को अग्रप्रेषित की गई थी। वीपीटी से एक सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था।
- (ii) संयुक्त सुनवाई में, जिंदल स्टेनलैस स्टील लि. (जेएसएसएल) के अनुरोध पर वीपीटी को पृष्ठांकित प्रति के साथ वीपीटी के प्रस्ताव पर टीएएमपी को अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए जेएसएसएल को एक सप्ताह का समय दिया गया था। वीपीटी से जेएसएसएल से टिप्पणियां प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था।

7.1. उपर्युक्त कार्रवाई बिन्दु सं. 6.2(i) के संदर्भ में, सीसीआईएल ने अपने पत्र दिनांक 22 जनवरी 2019 द्वारा संयुक्त सुनवाई में अपनी लिखित टिप्पणियां पेश की थीं। इसके अलावा, आरएचआई क्लासिल प्रा. लि. (आरसीपीएल) ने अपने पत्र दिनांक 22 जनवरी 2019 द्वारा अपनी टिप्पणियां भेजी थीं। सीसीआईएल और आरसीपीएल से प्राप्त टिप्पणियां वीपीटी को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रप्रेषित की गई थीं। वीपीटी ने अपे ईमेल दिनांक 12 फरवरी 2019 द्वारा अपना जवाब भेजा था।

7.2. उपर्युक्त कार्रवाई बिन्दु सं. 6.2(ii) के संदर्भ में, हालांकि जेएसएसएल को उसकी टिप्पणियां भेजने के लिए उसके अनुरोध पर एक सप्ताह अर्थात् 30 जनवरी 2019 तक का समय दिया गया था, परंतु इस मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक जेएसएसएल की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं।

7.3. वीपीटी ने अपने ईमेल दिनांक 14 मार्च 2019 द्वारा स्पष्ट किया था कि आयात ओवरसीज कंटेनर आयातित/उतारे गए विदेशी कंटेनर होते हैं और पोतांतरण कंटेनरों से इतर टर्मिनल से डिलीवरी लिये जाते हैं जिसका अर्थ दूसरे पोत पर पुनः लदाई।

8. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये व्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाये जाएंगे।

9. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:—

- (i) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा दाखिल प्रस्ताव वीपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु है। यह प्रस्ताव भारतीय पत्तन एसोसिएशन (आईपीए) की शासी निकाय बैठक में लिए गए निर्णय से आया है कि पत्तन कंटेनरों के आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और सीमाशुल्क द्वारा यथा स्वीकृत मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टमों की खरीद और संस्थापन करेंगे। पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा अपने पत्र दिनांक 12 जुलाई 2018 द्वारा, पत्तन में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग की संस्थापना के संबंध में आईपीए द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए, पांच महापत्तन न्यासों अर्थात् वीपीटी, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी), पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी), न्यू मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) को संप्रेषित किया था कि लागत की वसूली के लिए मानक संबंधी दरों का अनुसरण करें और प्रशुल्क के निर्धारण के लिए टीएएमपी को प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- (ii) यह प्रस्ताव प्रशुल्क नीति, 2015 को कार्यान्वित करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 5.7.1. के अधीन दाखिल किया बताया गया है। प्रशुल्क नीति, 2015 को कार्यान्वित करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देशों का खंड 5.7.1 विनिर्दिष्ट करता है कि जब संबद्ध महापत्तन न्यास के दरमान में सेवा/कार्गो के लिए प्रशुल्क उपलब्ध नहीं हो तो पत्तन किसी अन्य महापत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए निर्धारित प्रशुल्क और कार्यनिष्पादन मानकों, यदि कोई हों, का अंगीकरण करते हुए उक्त नए कार्गो/सेवा/सुविधा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना हेतु पत्तन इस प्राधिकरण का रुख करेगा। यदि किसी महापत्तन न्यास में प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया हो अथवा निर्धारित दर परिकल्पित कार्गो/सेवा/सुविधा के लिए प्रतिनिधित्व नहीं करती है, पत्तन न्यास 2008 दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अथवा दरित क्षमता के आधार पर अथवा विकल्पतः लागत जमा 16 प्रतिशत प्रतिलाभ सूत्र के अधीन सर्वोत्तम क्षमता के संदर्भ में प्रस्ताव दाखिल कर सकता है।

इस संबंध में, यहां यह कहना प्रासंगिक है कि प्रशुल्क नीति, 2015 की वैधता एमओएस द्वारा 13 जनवरी 2018 को इसकी समाप्ति की तारीख से 25 दिसंबर 2018 तक विस्तारित की गई थी। वीपीटी ने नई प्रशुल्क नीति, 2018 के जारी होने से पहले वर्तमान प्रस्ताव दाखिल किया था जिसमें उस समय की मौजूदा 2015 की प्रशुल्क नीति के संदर्भ में कुछ संशोधन किए गए थे। दरमान के निर्धारण के लिए नई “महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु प्रशुल्क नीति, 2018” एमओएस द्वारा अपने पत्र सं. आईडब्ल्यूटी-II/28/2018-आईडब्ल्यूटी दिनांक 26 दिसंबर 2018 द्वारा जारी किया गया था जो 26 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति, 2018 को कार्यान्वित करने के लिए वर्किंग दिशानिर्देश इस प्राधिकरण द्वारा 30 जनवरी 2019 को राजपत्र सं. 29 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। पूर्व वर्किंग दिशानिर्देशों में निर्धारित उपर्युक्त खंड सं. 5.7.1. भी प्रशुल्क नीति, 2018 में खंड 7.6.1. रूप में निर्धारित किया

गया है जो 26 जनवरी 2018 से लागू हुई थी और प्रशुल्क नीति, 2018 को कार्यान्वित करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वर्किंग दिशानिर्देशों के खंड 5.7.1. में विनिर्दिष्ट किया जाना भी जारी रखा गया है। इस प्रकार, इस प्रस्ताव पर एमओएस द्वारा जारी प्रशुल्क नीति, 2018 जोकि 26 दिसंबर 2018 से लागू है, के अधीन कार्यवाही की गई है।

- (iii) वीपीटी मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर पहले ही खरीद चुका है और बताया गया है कि परीक्षण चल रहे हैं। वीपीटी के मौजूदा दरमानों (एसओआर) में इस मद के लिए प्रशुल्क निर्धारित नहीं है। पत्तन ने बताया है कि इसी सुविधा के लिए किसी अन्य महापत्तन न्यासी में प्रशुल्क उपलब्ध नहीं है। इसलिए, पत्तन ने 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित बृहत् सिद्धांतों जोकि प्रशुल्क नीति, 2018 के खंड 7.6.1. और 5.7.1. में निर्धारित पद्धतियों में से एक है और क्रमशः उक्त प्रशुल्क नीति पर वर्किंग दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए और मानदंड संबंधी प्रशुल्क पर पहुंचने के लिए एमओएस के निर्णय का पालन करते हुए भी मानदंड आधार पर व्यापक रूप से इस मद के लिए दर के निर्धारण हेतु इस प्राधिकरण के अनुमोदन की मांग की है।

यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि हालांकि कंटेनर स्कैनर के लिए 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं, परंतु पत्तन ने 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों का व्यापक रूप से अनुसरण करते हुए और दरित क्षमता के आधार पर मौजूदा प्रस्ताव दाखिल किया है। इस प्रकार की सुविधा के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित किन्हीं विशिष्ट मानदंडों के अभाव में, इस प्राधिकरण ने वीपीटी द्वारा अंगीकृत दृष्टिकोण के आधार पर मोबाइल एक्स-रे स्कैनर के परिचालन के लिए वीपीटी द्वारा मांग किए गए प्रशुल्क के निर्धारण की कार्यवाही के लिए आगे बढ़ा है। यहां पर यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि वीपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव कंटेनरों के आयात को स्कैन करने के लिए डीजीएफटी और सीमाशुल्क की अनिवार्य अपेक्षा का पालन करने के लिए है और प्रस्ताव वीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इस मामले की कार्यवाही के दौरान, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2019 द्वारा, मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजे थे जिसमें पत्तन ने मूल्यह्रास के अनुमानों को संशोधित किया है। इसलिए, इस मामले की कार्यवाही के दौरान पत्तन द्वारा प्रेषित सूचना/स्पष्टीकरण के साथ मूल्यह्रास के संशोधित अनुमानों के साथ वीपीटी के मूल प्रस्ताव दिनांक 4 दिसंबर 2018 पर विचार किया गया है।

- (iv) दरित क्षमता:

एक्स-रे कंटेनर स्कैनर की दरित उत्पादकता एक तरफ सीधे परिचालन आधार पर 40 फीट के 20 कंटेनर प्रति घंटा प्रति घंटा है। इस सुविधा के लिए उपलब्ध किसी विशिष्ट मानदंड के अभाव में, वीपीटी द्वारा मूल्यांकित दरित उत्पादकता पर विश्वास किया गया है।

2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सर्वोत्तम क्षमता कुल क्षमता का 70 प्रतिशत है। एक वर्ष में 365 दिनों के लिए दरित उत्पादकता पर 70 प्रतिशत के उक्त मानदंड को लागू करते हुए, वीपीटी ने दरित क्षमता 2,45,280 टीईयू मी.ट. प्रतिवर्ष (0.7 x 365 दिन x 24 घंटे x 20 संख्याएं x 2 टीईयू=2,45,280 टीईयू) की दर से मूल्यांकित किया है। दरित क्षमता वीपीटी द्वारा यथा मूल्यांकित 2,45,280 टीईयू प्रतिवर्ष सुविचारित की गई है।

- (v) पूंजी लागत:

कुल पूंजी लागत रु. 17.58 करोड़ अनुमानित की गई है जिसमें एक्स-रे स्कैनरों की लागत संबंधी रु. 15.49 करोड़, सिविल कार्यों के लिए रु. 1.82 करोड़, रोशनी सहित बिजली आपूर्ति के लिए रु. 0.21 करोड़ और फाइबर तथा सीसीटीवी नेटवर्क के लिए रु. 0.06 करोड़ शामिल हैं।

एक्स-रे स्कैनर की पूंजी लागत की गई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आईपीए द्वारा चिह्नित एल-1 बोलीदाता को पहले से जारी किए गए कार्य आदेश पर आधारित है। सिविल कार्य के लिए वीपीटी द्वारा अनुमानित पूंजी लागत कार्य आदेश पर आधारित है और पत्तन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। रोशनी सहित बिजली आपूर्ति, फाइबर और वीपीटी द्वारा सीसीटीवी नेटवर्क के लिए पत्तन द्वारा अनुमानित पूंजी लागत को भी पत्तन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित किया गया है। पत्तन ने बताया है कि प्रशुल्क निर्धारण में सुविचारित पूंजी लागत अनुमानन में जीएसटी घटक शामिल नहीं है क्योंकि जीएसटी के लिए क्रेडिट सिविल कार्यों की पूंजी लागत के सिवाय लिया जाएगा। इस स्थिति पर विश्वास किया गया है।

चूंकि पूंजी लागत का अनुमान वास्तविकताओं पर आधारित है और दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित किया गया है, इसलिए पत्तन द्वारा यथा अनुमानित पूंजी लागत पर विचार किया गया है।

- (vi) परिचालन लागतें:

- (क) बिजली लागत:

जैसाकि पहले बताया गया है, अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 में प्रस्तावित सुविधा के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं हैं। पत्तन ने बिजली लागत का अनुमान लगाने के लिए बिजली उपभोग के अनुमानन हेतु विस्तृत आधार तथा गणना भेजी है जोकि 4 (I) (क) में पूर्व पैरा में दिया गया है और इसलिए दोहराया नहीं गया है। विस्तृत गणना के साथ समर्थित वीपीटी द्वारा सुविचारित बिजली उपभोग पर विश्वास किया गया है।

बिजली की रु. 6.38 की बिजली इकाई दर दिसंबर 2018 के बिजली बिल के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वैधीकृत की गई है। पत्तन द्वारा प्रेषित विस्तृत परिकलन के आधार पर, पत्तन द्वारा अनुमानित रु. 18.58 लाख की बिजली लागत पर विचार किया गया है।

(ख) मरम्मत और अनुरक्षण लागत:

(i) सिविल परिसंपत्तियों पर:

कंटेनर स्कैनर गतिविधि के लिए मरम्मत और अनुरक्षण लागत वीपीटी द्वारा सिविल कार्यों की पूंजी लागत के 1 प्रतिशत की दर से अनुमानित किया गया है जोकि रु. 1,81,909 (अर्थात् रु. 1,81,90,940 का 1 प्रतिशत) परिगणित होता है। वीपीटी द्वारा अंगीकृत 1 प्रतिशत का मानदंड 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार है।

(ii) एक्स-रे स्कैनर पर वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (एएमसी):

वीपीटी ने बताया है कि एक्स-रे कंटेनर स्कैनर का जीवनकाल 15 वर्ष है। वीपीटी द्वारा खरीद किए गए एक्स-रे स्कैनर की दो वर्षों की गारंटी है और वीपीटी ने 8 वर्षों की अवधि के लिए उक्त सुविधा के वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों (एएमसी) के लिए करार किया है। पत्तन द्वारा प्रेषित दस्तावेजी साक्ष्य से यह देखा गया है कि दो वर्षों की गारंटी अवधि के बाद 8 वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वीपीटी ने 8 वर्षों की अवधि में रु. 8,60,49,809 की कुल अनुरक्षण लागत के औसत पर विचार करते हुए लागत गणना में रु. 1,07,56,226/- प्रतिवर्ष (रु.8,60,49,809/8 वर्ष) की दर से अनुरक्षण लागत पर विचार किया है।

जब वीपीटी से वारंटी के दौरान पहले दो वर्षों के लिए स्कैनर की अनुरक्षण लागत को अलग रखते हुए और स्कैनर के अनुरक्षण की प्रति टीईयू लागत को लेते हुए तीसरे वर्ष के लिए पृथक प्रशुल्क प्रस्तावित करने के लिए कहा गया था तो पत्तन ने स्पष्ट किया था कि समान सुविधा के लिए दो अलग-अलग प्रशुल्कों के निर्धारण हेतु प्रावधान नहीं है।

हालांकि पत्तन ने 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों को अंगीकृत किया है, परंतु एक्स-रे स्कैनर के लिए पत्तन ने दो वर्षों की गारंटी के बाद 8 वर्षों के लिए प्रस्तावित सुविधा हेतु एएमसी के आधार पर अनुमान लिया है और औसत लागत पर विचार किया है। चूंकि एएमसी दर दो वर्षों की गारंटी के बाद 8 वर्षों की अवधि के लिए करार की गई दर के अनुसार है, और यह भी स्वीकार करते हुए कि प्रस्तावित दर वीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है और किसी भी उपयोक्ता ने इस अनुमान पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है, इस मद का अनुमान इस तरह विचार किया गया है जैसे यह एक करार की गई दर हो। पत्तन ने परिचालन की शुरुआत से प्रस्ताव प्रशुल्क वसूल करने का प्रस्ताव किया है और प्रस्तावित दर वीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।

हालांकि उपस्कर का जीवनकाल 15 वर्ष परिकल्पित किया गया है, प्रस्ताव से यह देखा गया है कि गारंटी और एएमसी 10 वर्ष कवर करती है। जब वीपीटी से परिसंपत्ति के शेष जीवनकाल 5 वर्षों पर विचार नहीं किए जाने के कारण देने के लिए कहा गया था तो पत्तन स्पष्ट किया था कि जिस एजेंसी से करार किया गया है उसने केवल 8 वर्षों की गारंटी अवधि के बाद वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों के ब्योरे भेजे हैं। तथापि, पत्तन ने स्पष्ट किया है कि अपफ्रंट आधार पर इस कार्यवाही के अधीन निर्धारित प्रशुल्क लागू सूचकांकन के साथ शेष पांच वर्षों की अवधि पर लागू होगा। ऐसी स्थिति में, यह उल्लेख करने के लिए एक उपयुक्त टिप्पणी शामिल की गई है कि निर्धारित प्रशुल्क अनुवर्ती अनुच्छेद में यथा उल्लिखित वार्षिक सूचकांकन के अधीन 15 वर्षों के लिए एक्स-रे स्कैनर के जीवनकाल के लिए लागू होगा।

यह अनुमान लगाया गया है कि पत्तन ने आठ वर्षों की अवधि के लिए एएमसी पर यह उपकरण देते समय यह मॉनीटर करने के लिए पर्याप्त मैकेनिज्म और चैक हैं कि आउटसोर्स किया गया ठेकेदार पर्याप्त ध्यान रखता है और परिसंपत्तियों का ध्यानपूर्वक अनुरक्षण करता है ताकि उपस्कर का जीवनकाल 15 वर्ष रह सके।

(iii) बिजली उपस्कर पर:

बिजली उपस्कर तथा फाइबर एवं सीसीटीवी नेटवर्क के लिए मरम्मत और अनुरक्षण लागत पूंजी लागत के 1 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है। वीपीटी द्वारा अंगीकृत 2 प्रतिशत का मानदंड 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार है।

(ग) बीमा लागत सकल अचल परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत की दर से अनुमानित की गई है जोकि दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड के अनुसार है।

(घ) मूल्यहास:

वीपीटी ने मूल प्रस्ताव में रु. 1,17,18,409 प्रतिवर्ष की दर से मूल्यहास का अनुमान लगाया था।

तत्पश्चात, वीपीटी ने विभिन्न परिसंपत्तियों के तत्संबंधी जीवनकाल पर विचार करते हुए अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2019 द्वारा मूल्यहास के अनुमान को संशोधित कर रु. 1,09,39,188 प्रतिवर्ष किया था और इस संबंध में विस्तृत गणना भेजी थी जोकि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई है और इसलिए संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए दोहराया नहीं गया है।

पत्तन ने पुष्टि की है कि कम्पनी अधिनियम के अनुसार कोई अतिरिक्त स्थानांतरण मूल्यहास नहीं दिया गया है क्योंकि सुविधा की सभी परिसंपत्तियां अतिरिक्त स्थानांतरण मूल्यहास नहीं (एनईएसडी) की श्रेणी के अधीन आते हैं। वीपीटी ने पुष्टि की है कि पत्तन द्वारा अनुमानित मूल्यहास कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित जीवनकाल मानदंडों के अनुसार है। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, वीपीटी द्वारा मूल्यहास लागत का संशोधित अनुमान रु. 1.09 करोड़ की दर से विचार किया गया है। हालांकि पत्तन ने मूल्यहास के संशोधित अनुमान भेजे हैं, परंतु लागत विवरण में उपयुक्त शोधन नहीं किया है। हमारे द्वारा तैयार किया गया लागत विवरण पत्तन द्वारा प्रेषित मूल्यहास के संशोधित अनुमान से अद्यतन किया गया है।

(ड) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओसीई):

2008 के अप्रकृत प्रशुल्क दिशानिर्देशों का खंड 2.4 आरओसीई 16 प्रतिशत की दर से अनुमत किए जाने की अपेक्षा करता है। वीपीटी ने पूंजी लागत की वसूली करने के लिए 6.67 प्रतिशत की दर से आरओसीई का अनुमान लगाया है। 6.67 प्रतिशत का आधार वीपीटी द्वारा स्पष्ट किया गया है। एक्स-रे स्कैनर का जीवनकाल 15 वर्ष है। इसलिए (100/15) 6.67 प्रतिशत उक्त उपस्कर के जीवनकाल में पूंजी लागत को वसूल करने के लिए पत्तन द्वारा दावाकृत प्रतिलाभ है। प्रस्तावित प्रशुल्क की वसूली द्वारा लागत की वसूली करने के लिए वीपीटी द्वारा आरओसीई के निम्नतर स्तर पर विचार किया गया है क्योंकि यह डीजीएफटी की अनिवार्य आवश्यकता है और लॉजिस्टिक लागत को साध्य स्तर तक कम करने के लिए है।

वीपीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मूल्यहास केवल परिचालन तथा अनुरक्षण लागत के घटक के रूप में ही सुविचारित किया गया है। 6.67 प्रतिशत का आरओसीई परियोजना के जीवनकाल के दौरान सुविधा की पूंजी लागत को वसूल करने के लिए है। 6.67 प्रतिशत के कम किए गए आरओसीई के साथ पत्तन द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क भी वीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। पत्तन द्वारा स्पष्ट किए गए उपर्युक्त बिन्दुओं के मद्देनजर, यह प्राधिकरण पत्तन द्वारा अनुमानित स्तर पर आरओसीई पर विचार करता है।

(vii) उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, कुल वार्षिक लागत वसूली अपेक्षा वीपीटी द्वारा यथा अनुमानित रु. 3.73 करोड़ परिगणित होता है। मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु लागत विवरण **अनुबंध** रूप में संलग्न किया गया है।

(viii) 2,45,280 टीईयू प्रतिवर्ष की सर्वोत्तम प्रहस्तन क्षमता पर रु. 3.73 करोड़ की दर से अनुमानित कुल वार्षिक लागत वसूली अपेक्षा वसूल करने के लिए, दर पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित रु. 151.93 प्रति टीईयू परिगणित होती है। वीपीटी ने मूल प्रस्ताव दिनांक 4 दिसंबर 2018 में रु. 155.11 प्रति टीईयू की दर प्रस्तावित की है। तत्पश्चात्, पत्तन ने मूल्यहास के अनुमान को संशोधित किया था जिसके लिए पत्तन ने संशोधित लागत विवरण नहीं भेजा था। मूल्यहास के संशोधित अनुमान पर विचार करने के बाद प्रस्तावित दर रु. 151.93 परिगणित होती है जिसे लागत विवरण में दर्शाया गया है।

यहां उल्लेख करना प्रासंगिक है कि पत्तन का प्रस्ताव डीजीएफटी तथा सीमाशुल्क की अनिवार्य अपेक्षा का पालन करने के लिए है। इसके अलावा, पत्तन ट्रेड से उम्मीद करता है कि लगभग रु. 6000 प्रति कंटेनर की बचत की जाए क्योंकि स्कैन किए गए कंटेनर को सीमाशुल्क जांच के लिए सीएफएस में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, कंटेनरों को स्कैनिंग के बाद सीधे पत्तन डिलीवरी आधार पर निकासित किया जा सकता है। इससे पत्तन में कंटेनरों के वापसी समय में सुधार होगा। पत्तन के प्रस्ताव पर किसी की कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में, अधिकांश उपयोक्ताओं ने टिप्पणी की है कि वे वीपीटी में कंटेनर स्कैनर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार, यह प्राधिकरण वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित रु. 151.93 प्रति टीईयू की दर अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है। वीपीटी को सलाह दी जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशुल्क नीति, 2018 के अधीन अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए दाखिल किए जाने वाले लागत विवरण में उपयुक्त समायोजन करे कि सामान्य दरमान में संशोधन की मांग करते समय कंटेनर स्कैनर की प्रस्तावित सुविधा की लागत वसूली पुनर्गति नहीं हो।

(ix) पत्तन ने मामले की कार्यवाही के दौरान कहा था कि सभी आयात कंटेनरों से प्रस्तावित दर वसूल की जाएगी। स्कैनर स्कैनिंग के लिए रैंडम आधार पर कंटेनर उठायेगा। प्रस्तावित दर एकसमान रूप से वसूल की जाएगी भले ही आयात कंटेनर स्कैन किया गया हो अथवा नहीं। इस संदर्भ में, वीपीटी ने यह टिप्पणी प्रस्तावित की है कि एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के लिए अवसंरचना अधिभार/प्रशुल्क टीईयू में अभिव्यक्त सभी आयात ओवरसीज कंटेनर पर लागू होता है। ओवरसीज कंटेनर को वीपीटी द्वारा आयातित/उतारा गया विदेशी कंटेनर रूप में परिभाषित किया गया है और पोतांतरण कंटेनर से इतर टर्मिनल से बाहर डिलीवरी के लिए लिया गया है जिसका अर्थ दूसरे पोत में पुनः लदान है। अतः, प्रस्तावित टिप्पणी को यह उल्लेख करने के लिए मामूली संशोधन के साथ निर्धारित किया गया है कि मामले की कार्यवाही के दौरान पत्तन द्वारा बनाये रखी गई स्थिति के अनुसार "एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के लिए निर्धारित प्रशुल्क पोतांतरण कंटेनरों से इतर सभी आयात ओवरसीज कंटेनरों पर लागू है भले ही आयात कंटेनर स्कैन किया गया हो अथवा नहीं"। टिप्पणी में मामूली संशोधन इसके क्रियान्वयन में किसी विसंगति से बचाव के लिए है।

(x) पत्तन ने यह भी कहा है कि वीपीटी में परिचालन कर रहे कंटेनर टर्मिनल परिचालक अर्थात् विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) के मामले में, उक्त प्रभार वीसीटीपीएल द्वारा संग्रहीत किए जाएंगे और वीपीटी को भुगतान किए जाएंगे क्योंकि कंटेनर स्कैनर पर निवेश तथा इसका परिचालन पत्तन द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में एक टिप्पणी वीपीटी के दरमान में शामिल की गई है।

(xi) पत्तन को उम्मीद है कि कंटेनर स्कैनर 31 मार्च 2019 से परिचालन में आ जाएगा। पत्तन ने संबद्ध उपयोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि यदि स्कैनर 31 मार्च 2019 तक परिचालन में नहीं आता है तो समय आगे बढ़ाया जाएगा और 31 मार्च 2019 से काफी पहले संबद्ध उपयोक्ताओं को अवगत करवा दिया जाएगा और स्कैनर के उपयोग के बिना कंटेनरों का प्रहस्तन करने की उन्हें अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में डीजीएफटी से जरूरी अनुमति प्राप्त की जाएगी। ऊपर बताई गई स्थिति के मद्देनजर, यह प्राधिकरण निर्धारित दर वीपीटी में कंटेनर स्कैनर परिचालन में आने की तारीख से लागू करने का अनुमोदन देता है।

(xii) हालांकि वीपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन है और प्रशुल्क नीति, 2018 जोकि वर्तमान में लागू है, के अधीन कार्यवाही की गई है, यहां दोहराना प्रासंगिक है कि नई सेवा के लिए पत्तन द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क मानदंड संबंधी दृष्टिकोण और 2008 दिशानिर्देशों अप्रकृत प्रशुल्क के सिद्धांतों का अनुसरण कर रहा है जोकि नए कार्गो/सेवा के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु उक्त प्रशुल्क नीति के अधीन उपलब्ध विकल्पों में से एक है।

प्रशुल्क नीति, 2015 और 2018 के अधीन, प्रशुल्क प्रत्येक तीन वर्षों के बाद समीक्षा के अधीन है और प्रशुल्क में सूचकांकन कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन डब्ल्यूपीआई के 100 प्रतिशत है।

2008 दिशानिर्देशों के अधीन अप्रकृत प्रशुल्क के मामले में, प्रशुल्क परियोजना अवधि के लिए है और डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिशत की दर से स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन है।

चूंकि वीपीटी का प्रस्ताव 2008 के अप्रकृत प्रशुल्क दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का अनुसरण करता है, इसलिए वीपीटी ने स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन एक्स-रे स्कैनर के 15 वर्षों के जीवनकाल के लिए दर का प्रस्ताव किया है।

पत्तन ने एक सामान्य टिप्पणी प्रस्तावित की है कि निर्धारित प्रशुल्क को मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा परन्तु 1 जनवरी 2019 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रशुल्क सीमा का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमा प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक लागू होगी।

वीपीटी द्वारा प्रशुल्क गणना में सुविचारित अनुमानों से यह देखा गया है कि अधिकांश मदें नवंबर/दिसंबर 2018 से संबंधित इकाई दर पर आधारित हैं। इसलिए, यह प्राधिकरण, पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित, 1 जनवरी 2019 जैसे प्रत्येक वर्ष स्वतः समायोजन के लिए सुविचारित किए जाने हेतु आधार डब्ल्यूपीआई निर्धारित करने के लिए पत्तन के प्रस्ताव के साथ जाता है। इस प्रकार, इस संबंध में पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित टिप्पणी शामिल की गई है।

10.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण वीपीटी के मौजूदा दरमान में खंड 7 – अन्य सेवाओं के लिए प्रभार के अधीन अनुसूची 7.7. – वीपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रभार रूप में वीपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए निम्नलिखित अनुसूची अनुमोदित करता है:

“वीपीटी में मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रभार की अनुसूची:

विवरण	इकाई	दर (रु. में)
मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रभार	टीईयू	152.00

टिप्पणियाँ:

- (1) एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के लिए निर्धारित प्रशुल्क पोतांतरण कंटेनरों से इतर सभी आयात ओवरसीज कंटेनरों पर लागू है भले ही आयात कंटेनर स्कैन किया गया हो अथवा नहीं।
- (2) विशाखा कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (वीसीटीपीएल) द्वारा वीपीटी में परिचालित कंटेनर टर्मिनल के मामले में, उक्त प्रभार वीपीटीसीएल द्वारा संग्रहीत किया जाएगा और वीपीटी को भुगतान किया जाएगा क्योंकि कंटेनर स्कैनर पर निवेश और इसका परिचालन पत्तन द्वारा किया जा रहा है।
- (3) निर्धारित प्रशुल्क स्वतः वार्षिक सूचकांकन के अधीन इसके लागू होने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।
- (4) उपर्युक्त निर्धारित प्रशुल्क मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा परन्तु 1 जनवरी 2019 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिशत की सीमा तक। प्रशुल्क सीमा का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क सीमा प्रासंगिक वर्ष की 1 मई से आगामी वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होगी”।

10.2. वीपीटी को मौजूदा दरमान उपयुक्ततः संशोधित करने का निदेश दिया जाता है।

टी. एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./84/19]

अनुबंध

विशाखापत्तन पत्तन न्यास में एक्स-रे कंटेनर स्कैनिंग सिस्टम के परिचालन के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु लागत विवरण

(रु. में)

क्र.सं.	विवरण	वीपीटी द्वारा अपने मूल प्रस्ताव दिनांक 4-12-2019 में दिए गए अनुमान जिन्हें वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2019 द्वारा अनुमानित संशोधित मूल्यहास से अद्यतन	टीएएमपी द्वारा सुविचारित वीपीटी के अनुमान
I	सर्वोत्तम प्रहस्तन क्षमता		
	कुल सर्वोत्तम प्रहस्तन क्षमता (टीईयू प्रतिवर्ष)	2,45,280	2,45,280
	(0.7 x 365 दिन x 24 घंटे x 20 संख्याएं x 2 टीईयू)		
II	पूंजी लागत		
i.	एक्स-रे स्कैनर की पूंजी लागत (जीएसटी अतिरिक्त)	15,48,71,376	15,48,71,376
ii.	सिविल कार्यों की पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	1,81,90,940	1,81,90,940
iii.	रोशनी सहित बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	21,15,830	21,15,830
iv.	फाइबर तथा सीसीटीवी नेटवर्क के लिए पूंजी लागत (कार्य आदेश मूल्य के अनुसार)	5,97,990	5,97,990
	कुल पूंजी लागतें	17,57,76,136	17,57,76,136

III	परिचालन लागत		
i.	बिजली उपभोग	18,58,305	18,58,305
ii.	सिविल परिसंपत्तियों की मरम्मत और अनुरक्षण (सिविल परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत की दर से) (रू. सिविल कार्य की लागत 1,81,90,940 x सिविल कार्य का 1%)	1,81,909	1,81,909
iii.	पुर्जों सहित अभियांत्रिक और बिजली उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण		
	क) एक्स-रे स्कैनर की एएमसी जीएसटी अतिरिक्त (बीपीटी: रू.8,60,49,809 / 8 वर्ष)	1,07,56,226	1,07,56,226
	ख) बिजली कार्यों और फाइबर तथा सीसीटीवी नेटवर्क की मरम्मत और अनुरक्षण (पूँजी लागत के 2 प्रतिशत की दर से) (ओ एंड एम लागत रू.27,13,820 x 2%)	54,276	54,276
iv.	बीमा (@ सकल अचल परिसंपत्तियों का 1%) (सकल अचल परिसंपत्तियां रू.17,57,76,136 x 1%)	17,57,761	17,57,761
v.	मूल्यहास	1,09,39,188	1,09,39,188
	कुल परिचालन लागत	2,55,47,665	2,55,47,665
IV	आरओसीई (6.67 प्रतिशत की दर से 15 वर्षों में लागत वसूली)	1,17,18,409	1,17,18,409
V	कुल वार्षिक लागत वसूली अपेक्षा (III + IV)	3,72,66,074	3,72,66,074
VI	लागत प्रति टीईयू (V/II)	151.93	151.93

टिप्पणी: बीपीटी ने मूल प्रस्ताव दिनांक 4 दिसंबर 2018 में रू. 155.11 प्रति टीईयू की दर प्रस्तावित की थी। तत्पश्चात्, पल्लन ने मूल्यहास का अनुमान संशोधित किया था जिसके लिए पल्लन ने संशोधित लागत विवरण नहीं भेजा था। पल्लन द्वारा प्रेषित मूल्यहास के संशोधित अनुमान पर विचार करने के बाद प्रस्तावित दर रू. 151.93 परिगणित होती है।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 14th May, 2019

No. TAMP/77/2018-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of tariff for operation of Mobile X-ray container scanning system at VPT as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/77/2018-VPT

Visakhapatnam Port Trust

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of March 2019)

This case relates to proposal dated 4 December 2018 received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of tariff for operation of Mobile X-Ray Container Scanning system at VPT.

2.1. This Authority had vide Order No.TAMP/9/2016-VPT dated 21 June 2016 passed an Order relating to general revision proposal of VPT along with the revised Scale of Rates. This Order was notified in the Gazette of India on 22 July 2016 vide Gazette No.305. The said Order prescribes a tariff validity period till 31 March 2019.

2.2. The existing Scale of Rates of VPT approved by this Authority does not contain the tariff for operation of Mobile X-Ray Container Scanning system at VPT.

3.1. The main points made by VPT in its proposal are summarized below:

- (i) A decision has been taken in the Governing Body Meeting of IPA that the ports should procure and install Mobile X-Ray Container Scanning Systems as mandated by the Directorate General for Foreign Trade (DGFT) and Customs for import of containers. Tendering process was undertaken by IPA and ports are directed to place purchase order on the L-1 bidder finalised by IPA.

- (ii) Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.PD-14033/113/2015-PD.V dated 12.7.2018 (furnished as Appendix-A) has referred to the minutes of the meeting held in IPA on 12 June 2018 on execution of project for installation of Mobile X-ray Container Scanning at port. The MOS has in the said letter communicated to the Chairmen of Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), VPT, Paradip Port Trust (PPT), New Mangalore Port Trust (NMPT) and Kolkata Port Trust (KOPT), conveying the decision that ports will have to follow Normative rates for cost for recovery and take up the proposal with TAMP for fixation of Tariff.
- (iii) In this backdrop, the Board of Trustees of VPT vide Resolution No.142/2017-18 (furnished as Appendix-B) has approved a total amount of ₹29.68 crores towards procurement, installation and commissioning of one no. of Mobile X-ray Container Scanner including ₹10,15,38,775 (₹10.15 crores) towards annual maintenance charges for 8 years period, tax and duties from M/s.Smiths Detection (Asia Pacific) Pvt. Ltd. The Board of Trustees has also approved to levy infrastructure cess, if any, as per TAMP approved rates as per the MOS guidelines. Action is also initiated for installation of the equipment.
- (iv) Tariff for similar facility is not available in any other major port. As such, a proposal for fixation of tariff based on the rated capacity of the facility is prepared as per clause 5.7.1 of Tariff Working Guidelines, 2015. The VPT has requested to notify the tariff for the facility at VPT.

3.2. The costing for the tariff is as follows:

(i) **Capital Cost:**

I.	Capital cost of X-Ray Scanner (Excl. GST)	15,48,71,376
II.	Capital cost of civil works (As per work order value)	1,81,90,940
III.	Capital cost for providing power supply including illumination (As per work order value)	21,15,830
IV.	Capital cost for fiber and CCTV network (As per work order value)	5,97,990
	Total capital cost	17,57,76,136

Notes:

- No provision is made for miscellaneous cost of 5% on capital cost of civil and equipment cost as the costs are as per the actual work order value.
- The cost items of the Price Schedule of items & schedule of quantities communicated by IPA is inclusive of GST. However, the same is excluded since GST will be taken credit except on capital cost of civil works.

(ii) **Rated capacity:**

The rated capacity of the X-ray container scanner is 20 numbers of 40 feet containers per hour (based on one way straight through operation) as per scope of work.

Therefore, the capacity per annum works out as follows:

$$0.7 \times 365 \text{ days} \times 24 \text{ hours} \times 20 \text{ numbers} \times 2 \text{ TEUs} = 245,280 \text{ TEUs per annum.}$$

(iii) **Operation and Maintenance cost:**

(a) (i) Power:

An amount of ₹18,58,305/- per annum is estimated towards cost of power consumption for operation of the facility.

(ii) Fuel:

The facility does not consume any fuel hence considered as NIL.

(b) Repair and Maintenance:

- (i) Repair and Maintenance of civil assets is estimated @ 1% of all civil assets as per norms. Total cost of civil works is ₹1,81,90,940/-. As such cost of repair and maintenance of civil assets works out to ₹1,81,909/- per annum.

(ii) Mechanical and electrical equipment including spares:

- (a) The Guarantee period for the x-ray scanner is two years. Total maintenance cost for a period of 8 years post-guarantee period including IGST @ 18% is ₹10,15,38,775/- and excluding IGST ₹8,60,49,809/- for 8 years. Thus, the average expenditure per annum towards AMC of x-ray scanner excluding IGST worked out to ₹8,60,49,809/- ÷ 8 = 1,07,56,226.
- (b) Repair and maintenance of electrical equipment and fiber and CCTV network is considered @ 2% on capital cost as per norms. Thus, R&M Cost on ₹27,13,820/- works out to ₹54,276/- per annum.
- (c) **Insurance:**
The value of gross fixed assets is ₹17,57,76,136/-. Insurance @ 1% on gross fixed assets as per Norms works out to ₹17,57,761/- per annum.
- (d) **Depreciation:**
The categorisation of the facility is considered under "IV. Plant and Machinery (a) Plant and Machinery other than continuous process plant not covered under specific industries" of the Companies Act for which specified life period is 15 years. Depreciation is calculated accordingly which works out to ₹1,17,18,409/- per annum.
- (e) **License fee and Other Expenses:**
No provision for license fee and other expenses is made since the facility is being installed at VPT's cost in its premises to meet the mandatory requirement of DGFT and Customs. The Customs will take appropriate manning of Officers and other staff in each shift in similar lines to those MXCS systems installed earlier at other locations which are being operated by Customs on their own.
- (iv) **ROCE:**
As per TAMP norms, 16% ROCE is allowed. However, Ministry of Shipping Lr. No.PD-14033/113/2015-PD.V dated 12.7.2018 states that it was decided that port will have to follow Normative rates for cost recovery and take up the proposal with TAMP for fixation of Tariff. The life of the equipment is 15 years. As such, to recover the cost of the equipment during its life of 15 years, the ROCE works out to 6.67% (100/ 15 years)
- (v) **Annual Revenue Requirement:**

Sl. No.	Description	Amount (₹)
1.	Power consumption	18,58,305
2.	Repair and maintenance of civil assets	1,81,909
3.	Repair and maintenance of X- Ray scanner	1,07,56,226
4.	Repair and maintenance of electrical equipment	54,276
5.	Insurance	17,57,761
6.	Depreciation	1,17,18,409
7.	ROCE (Cost recovery in 15 years)	1,17,18,409
	Total	3,80,45,295

(vi) **Proposed Tariff:**

Therefore, tariff per TEU = ₹3,80,45,295 ÷ 2,45,280 = ₹155.11 per TEU.

4. While acknowledging the proposal, the VPT was requested vide our letter dated 21 December 2018 to furnish information/ clarification on the following few points latest by 4 January 2019. This was followed by reminders dated 1 February 2019. In response, the VPT has furnished the information/ clarification vide its letter dated 5 February 2019. A summary of information/ clarification sought by us and comments furnished by VPT thereon is tabulated below:

Sl. No.	Information/ clarifications sought by us	Reply furnished by VPT																																
I	Tariff Computation by VPT:																																	
	Operating Costs for X-Ray Container Scanner:																																	
(A)	Power Cost:																																	
	<p>The VPT has estimated power cost at ₹18,58,305 per annum. The port has stated that detailed statement is attached as Annexure-2. However, no such statement is found to have been attached to letter dated 4 December 2018. The VPT to furnish detailed working of power cost giving power consumption alongwith basis for the power consumption and the unit rate of power considered for estimating the power cost. Also, confirm whether unit rate of power is the prevailing rate and furnish copies of electricity bills of the last three months to support the unit rate adopted in the computation.</p>	<p>The detail statement of the estimated power cost is tabulated below. It is to confirm that the unit rate power is the prevailing rate. Copies of bills for the last 4 months are enclosed.</p> <p>I. Power Supply Arrangements:</p> <table><tr><td>(i)</td><td>Lighting 200 watts X 26 Nos.</td><td>5.2 KW x 12 Hrs</td><td>62.40 Kwh</td></tr><tr><td>(ii)</td><td>15 A Power Sockets X 04 Nos.</td><td>12 KW x 06 Hrs</td><td>72.00 Kwh</td></tr><tr><td>(iii)</td><td>18 Watts TLs x 10 Nos.</td><td>0.18 KW x 18 Hrs</td><td>3.24 Kwh</td></tr><tr><td>(iv)</td><td>50 Watts C/F x 10 Nos.</td><td>0.5 KW x 18 Hrs</td><td>9.00 Kwh</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>146.64 Kwh / Day</td></tr></table> <p>Electrical Consumption / Annum : 150 X 365: 54750 Units Expenditure / Annum : 54750 X 6.38 (i.e. 6.32+0.06) ₹3,49,305/-</p> <p>II. MXCS Power Consumption:</p> <table><tr><td>Power Requirement</td><td>40 KVA X 0.9</td><td>36 KW</td></tr><tr><td></td><td>36 KW X 18 Hrs</td><td>648 KWH / day</td></tr><tr><td>MXCS Power Consumption/ Annum</td><td></td><td>648 x 365 : 2,36,520 Units</td></tr><tr><td>Expenditure/ Annum :</td><td>236520 x 6.38 (i.e. 6.32 + 0.06)</td><td>₹15,09,000/-</td></tr></table> <p>A) Electrical Consumption / Annum (With MXCS) – (I + II) = ₹18,58,305/- B) Electrical Consumption/ Annum (Without MXCS) – I = ₹3,49,305/-</p>	(i)	Lighting 200 watts X 26 Nos.	5.2 KW x 12 Hrs	62.40 Kwh	(ii)	15 A Power Sockets X 04 Nos.	12 KW x 06 Hrs	72.00 Kwh	(iii)	18 Watts TLs x 10 Nos.	0.18 KW x 18 Hrs	3.24 Kwh	(iv)	50 Watts C/F x 10 Nos.	0.5 KW x 18 Hrs	9.00 Kwh				146.64 Kwh / Day	Power Requirement	40 KVA X 0.9	36 KW		36 KW X 18 Hrs	648 KWH / day	MXCS Power Consumption/ Annum		648 x 365 : 2,36,520 Units	Expenditure/ Annum :	236520 x 6.38 (i.e. 6.32 + 0.06)	₹15,09,000/-
(i)	Lighting 200 watts X 26 Nos.	5.2 KW x 12 Hrs	62.40 Kwh																															
(ii)	15 A Power Sockets X 04 Nos.	12 KW x 06 Hrs	72.00 Kwh																															
(iii)	18 Watts TLs x 10 Nos.	0.18 KW x 18 Hrs	3.24 Kwh																															
(iv)	50 Watts C/F x 10 Nos.	0.5 KW x 18 Hrs	9.00 Kwh																															
			146.64 Kwh / Day																															
Power Requirement	40 KVA X 0.9	36 KW																																
	36 KW X 18 Hrs	648 KWH / day																																
MXCS Power Consumption/ Annum		648 x 365 : 2,36,520 Units																																
Expenditure/ Annum :	236520 x 6.38 (i.e. 6.32 + 0.06)	₹15,09,000/-																																
(B)	Repair and Maintenance of Mechanical and electrical equipment including spares																																	
(i)	<p>The VPT has stated that the life of X-Ray Container Scanner is 15 years and that the guarantee period of equipment is 2 years. The VPT has considered the maintenance at ₹1,07,56,226/- per annum which is the proportionate total maintenance cost of 8 years period estimated at ₹8,60,49,809. From the Annexure – I furnished by VPT it is seen that post two years guarantee period, the Annual Maintenance Cost of the Scanner increases year on year basis at 10% from ₹88,78,958/- in the first year to ₹29,68,74,836/- in the eight year. In this context, please clarify the following:</p>																																	
(a)	<p>The reasons for not considering the balance period of life of the asset [15-(2+8)=5].</p>	<p>The firm in its proposal has furnished details of annual maintenance charges post guarantee period of 8 years only. Further, it is observed that the AMC charges have been escalated by 10% year on year for the 8 years post guarantee period. As such, the average of the AMC for the period of 8 years specified by the firm is considered as AMC per annum. The tariff fixed by TAMP is upfront and will be applied to the balance five year period also with applicable indexation.</p>																																
(b)	<p>The reasons for not applying the norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines, 2008 may be explained more specifically because the Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-14033/113/2015-PD-V dated 12 July 2018 requires VPT to decide normative rates for cost recovery of the X-Ray Container Scanner.</p>	<p>Since the firm clearly indicated the AMC for 8 years post guarantee period, it is opined to consider the average of the 8 year period towards AMC per annum.</p>																																

(c)	Since normative tariff is to be fixed for recovery of cost as per the advice of MOS, the normative tariff for the container scanner may have to be independent of the periodic review once in 3 years and may have to be kept constant for the entire life period of the scanner subject to annual indexation of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) The VPT is requested to furnish its comments in this regard.	The tariff is proposed as per 2008 guidelines; wherein as per clause 2.8 the tariff will be indexed to an extent of 60% of the WPI as notified by TAMP for the period of operation and may not be reviewed once in 3 years.																									
(d)	The proposed tariff rate for operation of X-Ray Container Scanner may have to be included in the General Scale of Rates (SOR) of VPT which is subject to review every 3 years under Tariff Policy, 2015. That being so, the reason for considering the average of the total maintenance cost for 8 years period post 2 years guarantee while arriving at the proposed tariff may be explained.	Same as above.																									
(e)	Recognising that this item is under warrantee and being estimated "nil" for the first two years, the VPT may consider to propose tariff for Scanner excluding maintenance cost of Scanner for the first two years and separate tariff for third year capturing per TEU cost of maintenance of Scanner at ₹30.68 (i.e. ₹7524541/245280 TEUs)	As per 2008 guidelines, there is no provision for fixation of two different tariffs for the same facility.																									
(C)	Depreciation: The VPT has estimated deprecation at ₹1,17,18,409 on the total capital cost for a period of 15 years. The total capital cost for 15 years period estimated at ₹17,57,76,136 is divided by 15 years to arrive at depreciation. The VPT has stated that it has considered the Categorisation of the facility under Schedule II of the Companies Act 2013 under IV-General rate applicable to plant and machinery. In this regard following points may be clarified:	<div>The depreciation duly reckoning the life norm for different assets separately is revised as follows: (In Rupees)</div> <table><tr><td>I.</td><td>Capital cost of X-Ray Scanner (Excl. GST)</td><td>15,48,71,376</td><td>15 Years</td><td>1,03,24,758</td></tr><tr><td>II.</td><td>Capital cost of Civil Works (As per work order value)</td><td>1,81,90,940</td><td>60 Years</td><td>3,03,182</td></tr><tr><td>III.</td><td>Capital cost of providing power supply including illumination (As per work order value)</td><td>21,15,830</td><td>10 Years</td><td>2,11,583</td></tr><tr><td>IV.</td><td>Capital cost for fibre and CCTV network (As per work order value)</td><td>5,97,990</td><td>6 Years</td><td>99,665</td></tr><tr><td></td><td></td><td>17,57,76,136</td><td></td><td>1,09,39,188</td></tr></table>	I.	Capital cost of X-Ray Scanner (Excl. GST)	15,48,71,376	15 Years	1,03,24,758	II.	Capital cost of Civil Works (As per work order value)	1,81,90,940	60 Years	3,03,182	III.	Capital cost of providing power supply including illumination (As per work order value)	21,15,830	10 Years	2,11,583	IV.	Capital cost for fibre and CCTV network (As per work order value)	5,97,990	6 Years	99,665			17,57,76,136		1,09,39,188
I.	Capital cost of X-Ray Scanner (Excl. GST)	15,48,71,376	15 Years	1,03,24,758																							
II.	Capital cost of Civil Works (As per work order value)	1,81,90,940	60 Years	3,03,182																							
III.	Capital cost of providing power supply including illumination (As per work order value)	21,15,830	10 Years	2,11,583																							
IV.	Capital cost for fibre and CCTV network (As per work order value)	5,97,990	6 Years	99,665																							
		17,57,76,136		1,09,39,188																							
(i)	The total capital cost includes civil works and electrical works. The Companies Act, 2013 provides separate life norms for different nature of assets. The VPT may therefore, apply the relevant rate of depreciation depending on nature of asset and give reference of the same.																										
(ii)	The depreciation rate for plant and machinery under Companies Act 2013 applying life norms of 15 years after considering 5% scrap value works out to 6.33% for single shift. For double shift the depreciation rate needs to be increased by 50% and for triple shift by 100%. Since the VPT has assessed optimal capacity of the X-Ray Container Scanner for 24 hours a day, the VPT may review the estimate of depreciation in the light of the above observation.	All the assets proposed as part of facility fall under the category NESD for which No Extra Shift Depreciation is provided as per Companies Act. As such no extra shift depreciation is envisaged.																									
(D)	Return on Capital Employed (ROCE):																										
	The VPT has proposed 6.67% ROCE to recover the cost of equipment. The VPT has already considered depreciation in the cost calculation to recover the cost of equipment. The VPT to therefore, justify the lower level of ROCE considered in the calculation than 16%	Depreciation is considered only as a component of O & M cost. It is envisaged to recover the capital cost of the facility during the life of the project. Accordingly, ROCE is considered as 100/15=6.67%. A lower level of ROCE is considered keeping in view the following:																									

	ROCE allowed by the Authority.	(i) To recover the cost by levy of infrastructure cess without any return since it is a mandatory requirement of the DGFT. (ii) To reduce the logistic cost to a feasible extent.
II.	Scale of Rates: The port has not furnished the conditionalities governing the tariff for operation of mobile X-Ray Container Scanning System at VPT. The VPT may therefore give the conditionalities governing the tariff, if any.	The following conditionalities will apply to the facility: (i) The infrastructure cess / tariff for X-Ray container scanning system is applicable to all import overseas container expressed in TEUS. (ii) The tariff / infrastructure cess will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 st January 2019 and 1 st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1 st April of the relevant year to 31 st March of the following year.

5. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the VPT proposal dated 4 December 2018 was circulated to the concerned users/ user organisations/ Importers/ CFS Agents. We have, however, not received any comments from users/ user organisations/ Importers/ CFS Agents despite reminder dated 15 January 2019.

6.1. A joint hearing in this case was held on 22 January 2019 at VPT premises. At the joint hearing, VPT made a power point presentation of its proposal. The users and the VPT made their submissions at the joint hearing.

6.2. As agreed at the joint hearing, the VPT was requested vide our letter dated 1 February 2019 to take action on the following points:

- (i) At the joint hearing, Container Corporation of India Ltd. (CCIL) has furnished their written submission dated 22 January 2019. A copy of the written submission made by CCIL was forwarded to VPT. The VPT was requested to furnish its comments within a week's time.
- (ii) At the joint hearing, at the request of Jindal Stainless Steel Ltd. (JSSL) one week's time was allowed to JSSL to furnish its comments to TAMP on the proposal of VPT with a copy endorsed to VPT. The VPT was requested to furnish its comments within three days on the receipt of comments from JSSL.

7.1. With reference to the action point no.6.2. (i) above, the CCIL vide its letter dated 22 January 2019 has furnished its written comments at the joint hearing. Further, RHI Clasil Pvt. Ltd (RCPL) vide its letter dated 22 January 2019 has also furnished its comments. The comments received from the CCIL and RCPL were forwarded to the VPT as feedback information. The VPT vide its e-mail dated 12 February 2019 has furnished its reply.

7.2. With reference to the action point no.6.2. (ii) above, though JSSL was granted one week's time sought by it to furnish its comments i.e. by 30 January 2019, no comments of JSSL are received till finalization of this case.

7.3. The VPT vide its e-mail dated 14 March 2019 has clarified that import overseas container refers to foreign containers imported/ landed and taken delivery out from terminal other than transshipment containers which are meant for reloading into another vessel.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

9. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i) The proposal filed by the Visakhapatnam Port Trusts (VPT) is for fixation of tariff for operation of Mobile X-Ray Container Scanning system at VPT. The proposal flows from the decision taken in the Governing Body Meeting of Indian Port Association (IPA) that the ports should procure and install Mobile X-Ray Container Scanning Systems as mandated by the Directorate General for Foreign Trade (DGFT) and Customs for import of containers. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter dated 12 July 2018 has, referring to the decision taken by the IPA regarding installation of Mobile X-ray Container Scanning at port, communicated to the five Major Port Trusts viz. VPT, Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT),

Paradip Port Trust (PPT), New Mangalore Port Trust (NMPT) and Kolkata Port Trust (KOPT) to follow Normative rates for recovery of cost and take up the proposal with TAMP for fixation of Tariff.

- (ii) The proposal is stated to have been filed under clause 5.7.1. of the Working Guidelines to operationalise the Tariff Policy, 2015. Clause 5.7.1 of the working guidelines to operationalise the Tariff Policy, 2015 stipulates that when a tariff for service/ cargo is not available in the SOR of the concerned Major Port Trust, the port shall approach this Authority for notification of tariff for the said new cargo/ service/ facility adopting the tariff and Performance Standards, if any, fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any other Major Port Trust. If there is no tariff prescribed in any Major Port Trust or the rate prescribed is not representative for the cargo/ service/ facility envisaged, the Port Trust may file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or alternatively under cost plus 16% return formula.

In this regard, it is relevant here to state that validity of the Tariff Policy, 2015 was extended by the MOS from date of its expiry on 13 January 2018 till 25 December 2018. The VPT has filed the current proposal prior to the issue of the new Tariff Policy, 2018 wherein few amendments have been made with reference to the then existing Tariff Policy of 2015. The new "Tariff Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2018" for determination of SOR was issued by the MOS vide its letter No.IWT-II/28/2018-IWT dated 26 December 2018 which has come into effect from 26 December 2018. The Working Guidelines to operationalise the Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018 for determination of tariff for Major Port Trusts has also been notified by this Authority in the Gazette of India vide Gazette No.29 on 30 January 2019. The above mentioned Clause no.5.7.1 prescribed in the earlier Working Guidelines is also prescribed as Clause 7.6.1. in the Tariff Policy, 2018 which has come into effect from 26 December 2018 and same provision is also continued to be stipulated in Clause No.5.7.1. of the Working Guidelines notified by this Authority to operationalise the Tariff Policy, 2018. This proposal is thus processed under the Tariff Policy, 2018 issued by the MOS which is effective from 26 December 2018.

- (iii) The VPT has already procured the Mobile X-Ray Container Scanner and reported that tests are going on. The existing Scale of Rates (SOR) of VPT does not prescribe tariff for this item. The Port has stated that tariff for similar facility is not available in any other Major Port Trusts. Hence, the VPT has sought approval of this Authority for fixation of rate for this item broadly on norm basis following the broad principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 which is one of the methods prescribed in clause 7.6.1 and 5.7.1 of the Tariff Policy, 2018 and Working Guidelines on the said Tariff Policy respectively and also to comply with the decision of the MOS to arrive at normative tariff.

It is relevant here to state that though there are no specific norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008 for Container Scanner, the Port has filed the current proposal broadly following the general principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 and based on the rated capacity. In the absence of any specific norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines for this kind of facility, this Authority proceeds to fix the tariff sought by the VPT for operation of mobile X- Ray Scanner based on the approach adopted by the VPT. It is also relevant here to state that the proposal has been filed by the VPT to comply with the mandatory requirement of DGFT and Customs to scan the import of containers and the proposal has been approved by the Board of Trustees of VPT.

During the processing of the case, the VPT has, vide its letter dated 5 February 2019, furnished additional information/ clarification sought wherein the port has modified estimates of Depreciation. Hence, the original proposal of the VPT dated 4 December 2018 with modified estimates of depreciation along with information/ clarification furnished by the port during the processing of the case is considered.

- (iv) **Rated Capacity:**

The rated productivity of the X-ray container scanner is 20 containers of 40 feet per hour based on one way straight through operation. In the absence of any specific norm available for this facility, the rated productivity assessed by the VPT is relied upon.

As per norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008, optimal capacity is 70% of the total capacity. Applying the said norm of 70% on the rated productivity for 365 days in a year, the VPT has assessed the rated capacity at 2,45,280 TEUs MT per annum (0.7 x 365 days x 24 hours x 20 numbers x 2 TEUs=2,45,280 TEUs) The rated capacity is considered as 2,45,280 TEUs per annum as assessed by the VPT.

(v) **Capital Cost:**

The total capital cost is estimated at ₹17.58 crores which comprises of ₹15.49 crores towards cost of X-Ray Scanners ₹1.82 crores towards Civil works, ₹0.21 crores towards power supply including illumination and ₹0.06 cost towards fiber and CCTV network.

The capital cost X-Ray Scanner is based on work order already issued to the L1 bidder identified by the IPA through tendering process done. The capital cost estimated by VPT for civil work is based on work order and is substantiated by the port with documentary evidence. The capital cost estimated by the port towards power supply including illumination, fiber and CCTV network by VPT is also substantiated by the port with documentary evidences. The port has stated that capital cost estimation considered in tariff fixation is excluding the GST component since credit for GST will be taken except on capital cost of civil works. This position is relied upon.

Since the estimate of capital cost are based on actuals and substantiated with documentary evidence, the capital cost is considered as estimated by the port.

(vi) **Operating costs:**(a) Power Cost:

As stated earlier, there are no specific norms prescribed for the proposed facility in the upfront tariff guidelines, 2008. The port has furnished detailed basis and working for estimation of power consumption for estimating the power cost which is brought out in earlier para at 4 (I) (a) and hence not reiterated. The power consumption considered by the VPT supported with detailed working is relied upon.

The unit rate power of ₹6.38 for per unit of power is validated based on a documentary evidence of electricity bill of December 2018. Based on the detailed computation furnished by the port, the power cost of ₹18.58 lakhs estimated by the port is considered.

(b) Repairs and Maintenance Cost:(i) On Civil Assets:

Repairs and maintenance cost for container scanner activity is estimated at 1% of the capital cost of civil works by VPT which works out to ₹1,81,909 (i.e. 1% of ₹1,81,90,940) The norm of 1% adopted by VPT is in line with the norm prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008.

(ii) Annual Maintenance Charges (AMC) on X-Ray Scanner:

The VPT has stated that the life of X-Ray Container Scanner is 15 years. The X-Ray Scanner procured by VPT is under two years guarantee and VPT has contracted for Annual Maintenance Charges (AMC) of the said facility for a period of 8 years. It is seen from the documentary evidence furnished by the port that the AMC is escalated by 10% year on year basis for the 8 years post two years guarantee period. The VPT has considered the maintenance cost at ₹1,07,56,226/- per annum in the cost calculation considering the average of total maintenance cost of ₹8,60,49,809 over period of 8 years (₹8,60,49,809 / 8 years)

When the VPT was sought to propose tariff for Scanner excluding maintenance cost of Scanner for the first two years during the warrantee and separate tariff for third year capturing per TEU cost of maintenance of Scanner, the port has clarified that there is no provision for fixation of two different tariffs for the same facility.

Though port has adopted the norms prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008, for X-Ray Scanner the port has taken estimate based on AMC for the proposed facility for 8 years post two years guarantee and considered the average cost. Since the AMC rate is as per the contracted rate for period of 8 years post two years guarantee, and also recognising that the proposed rate is approved by the Board of Trustees of the VPT and none of the users have raised any objection on this estimate, the estimate of this item is considered as it is a contracted rate. The port has proposed to recover the

proposed tariff from the commencement of operation and the proposed rate is approved by the Board of Trustees of the VPT.

Though the life the equipment is envisaged to be for 15 years, from the proposal it is seen that the guarantee and AMC covers 10 years. When the VPT was sought to give reasons for not considering the balance period of life of the asset of 5 years, the port has clarified that the contracted agency has furnished details of annual maintenance charges post guarantee period of 8 years only. The port has, however, clarified that the tariff fixed under this exercise on upfront basis will be applied to the balance five year period also with applicable indexation. That being so, a suitable note is inserted to state that the tariff prescribed shall be applicable for the life of the X-Ray scanner for 15 years subject to annual indexation as brought out in the subsequent paragraph.

It is presumed that the port while giving this equipment on AMC for a period of eight years has sufficient mechanism and checks to monitor that the outsourced contractor takes adequate care and maintains the assets diligently so that the equipment has life of 15 years.

(iii) On Electrical Equipment:

Repairs and maintenance cost for electrical equipment and fibre and CCTV network is estimated at 2% of the capital cost. The norm of 2% adopted by VPT is in line with the norm prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008.

- (c) Insurance cost is estimated at 1% of the gross fixed assets, which is in line with the norm prescribed in the guidelines.

(d) Depreciation:

The VPT in the original proposal had estimated depreciation at ₹1,17,18,409 per annum.

Subsequently, the VPT vide its letter dated 5 February 2019 has modified the estimate of depreciation to ₹1,09,39,188 per annum considering the respective life of different assets and has furnished detailed working in this regard which has been brought out in the earlier paragraphs and hence not reiterated for sake of brevity.

The Port has confirmed that no extra shift depreciation is provided as per Companies Act as all the assets of the facility fall under the category of No Extra Shift Depreciation (NESD) The VPT has confirmed that the depreciation estimated by Port is in line with the life norms prescribed in the Companies Act, 2013. In view of the above position, the revised estimate of depreciation cost by VPT at ₹1.09 crores is considered. Though the port has furnished revised estimate of depreciation, it has not made suitable correction in the cost statement. The cost statement prepared by us is updated with the modified estimation of depreciation furnished by the port.

(e) Return on Capital Employed (ROCE):

Clause 2.4. of the upfront tariff guidelines of 2008 requires to allow ROCE at 16%. The VPT has estimated ROCE @ 6.67% to recover the capital cost. The basis of 6.67% is explained by the VPT. The life of the X-Ray scanner is 15 years. Hence (100/15) 6.67% is the return claimed by the port to recover the capital cost over the life of the said equipment. A lower level of ROCE is considered by VPT to recover the cost by levy of the proposed tariff since it is a mandatory requirement of the DGFT and to reduce the logistic cost to a feasible extent.

The VPT has further clarified that depreciation is considered only as a component of Operation and maintenance cost. ROCE of 6.67% is to recover the capital cost of the facility during the life of the project. The tariff proposed by the port with reduced ROCE of 6.67% is also approved by the Board of Trustees of the VPT. In view of the above points clarified by the port, this Authority considers the ROCE at the level estimated by the port.

- (vii) Based on the above analysis, the total annual cost recovery requirement works out to ₹3.73 crores as estimated by the VPT. The cost statement for fixing tariff for operation of Mobile X-Ray Container Scanning System is attached as **Annex**.

- (viii) In order to recover the total annual cost recovery requirement estimated at ₹3.73 crores over the optimal handling capacity of 2,45,280 TEUs per annum, the rate works out at ₹151.93 per TEU as proposed by the port. The VPT in the original proposal dated 4 December 2018 has proposed rate of ₹155.11 per TEU. Subsequently, the port modified the estimate of depreciation for which the port has not furnished modified cost statement. The proposed rate after considering the modified estimate of depreciation works out to ₹151.93 which is reflected in the cost statement.

It is relevant here to state that proposal of the port is to comply with the mandatory requirement of DGFT and Customs. Further, the port expects the trade to save around ₹6,000 per container as the scanned container need not go to CFS for custom examination. Moreover, containers can be cleared on Direct Port Delivery basis after scanning. This will improve the turn-around time of containers at the port. There has not been any objection on the proposal of the port. In fact, most of the users have commented that they are waiting for the container scanner to come in VPT. Thus, this Authority is inclined to approve the rate of ₹151.93 per TEU as proposed by the VPT. The VPT is advised to make appropriate adjustment in the cost statement to be filed for general revision of its SOR under Tariff Policy, 2018 to ensure that there is no duplication of cost recovery of the proposed facility of container scanner while seeking revision on the general SOR.

- (ix) The port has stated during processing of the case that all import containers shall be charged the proposed rate. The scanner will pick up container at random for scanning. The proposed rate will be charged uniformly irrespective of whether import container is scanned or not. In this context, the VPT has proposed a note stating that the infrastructure cess/ tariff for X-Ray container scanning system is applicable to all import overseas container expressed in TEUs. The overseas container has been defined by the VPT as a foreign container imported/ landed and taken delivery out from terminal other than transshipment container which is meant for reloading into another vessel. Therefore, the proposed note is prescribed with slight modification to state that "The tariff prescribed for X-Ray container scanning system is applicable to all import overseas containers other than transshipment containers irrespective of whether import container is scanned or not" in line with position maintained by the port during processing of the case. The slight modification in the note is to avoid any ambiguity in its application.
- (x) The port has also stated that in respect of the Container Terminal Operator operating in the VPT viz. Visakha Container Terminal Private Limited (VCTPL), the said charges shall be collected by VCTPL and paid to VPT since the investment on container scanner and its operation is being done by the port. A note in this regard is included in the SOR of the VPT.
- (xi) The port expects Container Scanner to come into operation by 31 March 2019. The port has assured the users concerned that if scanner is not operational by 31 March 2019, then the time will be extended and made known to the concerned users well before 31 March 2019 allowing them to handle containers without use of scanner and port shall seek necessary permission from DGFT in this regard. In view of the position brought out above, this Authority approves the prescribed rate effective from the date the Container Scanner becomes operational at the VPT.
- (xii) Though the proposal filed by the VPT is under the Tariff Policy, 2015 and processed under Tariff Policy, 2018 which is presently applicable, it is relevant here to reiterate that the tariff proposed the port for the new service is following the normative approach and the principles of upfront tariff of 2008 guidelines which is one of the options available under the said Tariff Policy for fixing tariff for new cargo/ service.

Under the Tariff Policy, 2015 and 2018, the tariff is subject to review after every three years and indexation in tariff is at 100% of the WPI subject to achievement of performance standards.

In case of upfront tariff under 2008 guidelines, the tariff is for the project period and is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI.

Since the proposal of the VPT follows the principles of the upfront tariff Guidelines of 2008, the VPT has proposed the rate for the life of the X-Ray scanner which is 15 years subject to automatic annual indexation.

The port has proposed a general note that the prescribed tariff will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2019 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap

will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st April of the relevant year to 31st March of the following year.

It is seen from the estimates considered in the tariff calculation by VPT that for many of the items are based on the unit rate pertaining to November/ December 2018. Hence, this Authority goes with the proposal of the port to prescribe the base WPI to be considered for automatic adjustment every year as 1 January 2019, as proposed by the Port. Thus, the note in this regard as proposed by the Port is incorporated.

10.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following Schedule for operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at VPT as Schedule 7.7 - Charges for Operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at VPT under Section 7 - Charges for Other Services in the existing Scale of Rates of VPT:

“Schedule of charge for Operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at VPT:

Description	UNIT	Rate (in ₹)
Charges for Operation of Mobile X-Ray Container Scanning System	TEU	152.00

Notes:

- (1) The tariff prescribed for X-Ray container scanning system is applicable to all import overseas containers other than transshipment containers irrespective of whether an import container is scanned or not.
- (2) In respect of the Container Terminal operated in the VPT by Visakha Container Terminal Limited (VCTPL), the said charge shall be collected by VCTPL and paid to VPT since the investment on container scanner and its operation is being done by the port.
- (3) The tariff prescribed will be valid for period of 15 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation.
- (4) The tariff prescribed above will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January 2019 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year.”

10.2. The VPT is directed to amend the existing SOR suitably.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.III/4/Exty./84/19]

Annex

COST STATEMENT FOR FIXATION OF TARIFF FOR OPERATION OF X-RAY CONTAINER SCANNING SYSTEM AT VISAKHAPATNAM PORT TRUST

(in Rs.)

Sl. No.	Particulars	Estimates by VPT in its original proposal dated 4.12.2019 updated with modified depreciation estimated by VPT vide its letter dated 5 February 2019	Estimates of VPT considered by TAMP
I	<u>Optimal handling capacity</u>		
	Total Optimal handling capacity say (TEUs per annum)	2,45,280	2,45,280
	(0.7 x 365 days x 24 Hours x 20 numbers x 2 TEUs)		
	-		
II	<u>Capital Cost</u>		
i.	Capital Cost of X-Ray Scanner (Excl. GST)	15,48,71,376	15,48,71,376
ii.	Capital Cost of Civil Works (As per work order value)		

		1,81,90,940	1,81,90,940
iii.	Capital Cost for providing power supply including illumination (As per work order value)	21,15,830	21,15,830
iv.	Capital Cost for fibre and CCTV network (As per work order value)	5,97,990	5,97,990
	-		
	Total Capital costs	17,57,76,136	17,57,76,136
III	<u>Operating Cost</u>		
i.	Power consumption	18,58,305	18,58,305
ii.	Repair and Maintenance of Civil assets (@ 1% of Civil assets) (Rs. Cost of civil work 1,81,90,940 x 1% of civil work)	1,81,909	1,81,909
iii.	Repair and Maintenance of mechanical and electrical equipment including spares		
	a) AMC of X-Ray scanner excluding GST (VPT: Rs.8,60,49,809 / 8 years)	1,07,56,226	1,07,56,226
	b) Repair and Maintenance of electrical works and fibre and CCTV network (@ 2% of Capital Cost) (O&M Cost Rs.27,13,820 x 2%)	54,276	54,276
iv.	Insurance (@1% of gross fixed assets) (Gross fixed assets Rs.17,57,76,136 x 1%)	17,57,761	17,57,761
v.	Depreciation	1,09,39,188	1,09,39,188
	Total Operating Cost	2,55,47,665	2,55,47,665
IV	ROCE (Cost recovery in 15 years @ 6.67%)	1,17,18,409	1,17,18,409
V	Total Annual cost recovery Requirement (III + IV)	3,72,66,074	3,72,66,074
VI	<u>Cost per TEU (V/I)</u>	151.93	151.93

NOTE: The VPT in the original proposal dated 4 December 2018 has proposed rate of Rs.155.11 per TEU. Subsequently, the port modified the estimate of depreciation for which the port has not furnished modified cost statement. The proposed rate works out to Rs.151.93 after considering the modified estimate of depreciation furnished by the port.